



राज्यपाल सचिवालय, बिहार
(जन-सम्पर्क शाखा)
राजभवन, पटना-800022

ई-मेल—pr.rajbhavan@gmail.com
prrajbhavanbihar@gmail.com
मोबाईल—9431283596

प्रेस-विज्ञप्ति

राजभवन में 'यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इनफॉर्मेशन सिस्टम' के कार्यान्वयन की तैयारियों की समीक्षा की गई

पटना, 08 मई 2019

महामहिम राज्यपाल-सह-कुलाधिपति श्री लाल जी टंडन के निदेशानुरूप आज राजभवन सभाकक्ष में राज्य के विश्वविद्यालयों में 'University Management Information System-UMIS' के कार्यान्वयन की तैयारियों की समीक्षा की गई।

बैठक में अपने संबोधन के दौरान राज्यपाल के प्रधान सचिव श्री विवेक कुमार सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि इस बार के शैक्षणिक सत्र से ही सभी विश्वविद्यालयों में यू.जी.-पी.जी. तथा अन्य सभी पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया हर हालत में प्रारंभ कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आवेदन से लेकर नामांकन तक सभी प्रक्रियाएँ ऑन-लाईन पूरी करने के अलावे, 'स्टूडेंट्स एवं टीचर्स लाइफ-साईकिल' से जुड़े सभी कार्य 'UMIS' के तहत पूरी तरह कम्प्यूटराइज्ड हों, इसके लिए पूरे पैकेज को एक साथ लागू किया जाना जरूरी है। प्रधान सचिव ने कहा कि 'UMIS' व्यवस्था के तहत तत्काल हर हालत में सभी विश्वविद्यालयों को यू.जी. में नामांकन-प्रक्रिया पूरी करनी है; जिसके लिए चयनित कार्यकारी एजेंसी एवं विश्वविद्यालयों के नोडल पदाधिकारियों को समन्वयपूर्वक कार्य करना होगा। प्रधान सचिव ने कहा कि महामहिम राज्यपाल के निदेश के अनुपालन में थोड़ी भी शिथिलता को गंभीरता से लिया जाएगा तथा जिम्मेवार अधिकारियों को चिह्नित कर दंडित किया जायेगा।

आज की बैठक में समीक्षा के दौरान यह बात स्पष्ट हुई कि पूर्णिया विश्वविद्यालय, पूर्णिया, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, बी.आर.ए.बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय को छोड़कर अन्य सभी विश्वविद्यालयों में 'यू.एम.आई.एस.' के कार्यान्वयन की तैयारियाँ संतोषजनक हैं। पूर्णिया विश्वविद्यालय के यू.एम.आई. के नोडल पदाधिकारी ने बताया कि निविदा-प्रक्रिया पूरी कर अभी तक कार्यादेश निर्गत नहीं किया जा सका है तथा वहाँ अर्थ की भी समस्या आड़े आ रही है। इस संदर्भ में नोडल पदाधिकारी को राजभवन द्वारा पूर्व में दिए गए मार्ग-दर्शनों का स्मरण कराते हुए कहा गया है कि इसी शैक्षणिक सत्र से हर हालत में महामहिम कुलाधिपति के आदेशालोक में यू.एम.आई.एस. व्यवस्था लागू होनी है। नोडल पदाधिकारी से पूछा गया कि अन्य विश्वविद्यालय भी राज्य सरकार द्वारा प्राप्त प्रारंभिक राशि 10 लाख रुपये की राशि से ही जब कार्यांभ करा चुके हैं, तब पूर्णिया विश्वविद्यालय के लिए क्यों कठिनाई है? उन्हें स्पष्ट हिदायत दी गई कि कार्यकारी एजेंसी नियमानुरूप चुनते हुए अविलम्ब कार्यादेश निर्गत होना चाहिए तथा यू.एम.आई.एस. के कार्यान्वयन का मार्ग शीघ्र प्रशस्त होना चाहिए। वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा के प्रतिनिधि ने बताया कि कुछ प्रक्रियागत कठिनाइयों के कारण उन्हें दुबारा निविदा निकालनी पड़ी है। वी.के.एस.यू. आरा के नोडल पदाधिकारी को शीघ्र निविदा निष्पादित कराते हुए कार्यांभ कराने का निदेश दिया गया ताकि यू.जी. एडमिशन में अनावश्यक विलम्ब न हो। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि पदाधिकारी ने बताया कि एन.आई.सी. के जरिये उनके यहाँ यू.एम.आई.एस. का कार्यान्वयन किया जायेगा। बैठक में समीक्षा के दौरान बाबासाहेब भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर में भी यू.एम.आई.एस. संबंधी कार्यादेश नहीं निकल पाने पर असंतोष व्यक्त किया गया।

आगे पृष्ठ...2 पर

(2)

समीक्षा के दौरान टी.एम.बी.यू., भागलपुर एवं बी.एन.एम.यू., मधेपुरा विश्वविद्यालय में 'UMIS' के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त किया गया। अन्य विश्वविद्यालयों को भी शीघ्र कार्यादेश निर्गत कर इस व्यवस्था का पूर्णतः कार्यान्वयन सुनिश्चित करने को कहा गया।

बैठक को संबोधित करते हुए राज्यपाल के प्रधान सचिव ने सभी विश्वविद्यालयों को 'UMIS' व्यवस्था के तहत राज्यपाल सचिवालय एवं राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग को लिंक प्रदान करते हुए 'यूजर-आई.डी.' और 'यूजर-पासवर्ड' शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया ताकि व्यवस्था की सतत मोनिटरिंग की जा सके।

प्रधान सचिव ने कहा कि जिन 4 विश्वविद्यालयों में यू.एम.आई.एस. के कार्यान्वयन में संतोषजनक प्रगति नहीं पाई गई है, उनके पदाधिकारियों की पुनः 15 मई को राजभवन में बैठक आयोजित की जाये तथा अनुपालन-स्थिति की समीक्षा की जाये। बैठक में प्रधान सचिव ने सभी नोडल पदाधिकारियों को निदेश दिया कि हरेक विश्वविद्यालय से प्रत्येक दिन शाम में दिन भर की उपलब्धियों पर आधारित एक 'Summary Report' आनी चाहिए।

आज की बैठक में संयुक्त सचिव श्री विजय कुमार, ओ.एस.डी. श्री अहमद महमूद, राजभवन एन.आई.सी. प्रभारी श्री विजय कुमार सहित सभी विश्वविद्यालयों के नोडल पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।

.....